



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2015/आषाढ़ 30, 1937

No. 457]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2015/ASHADHA 30, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

सं. 40/2015-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 568(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले काटे और तराशे गए हीरों पर, जब इनका आयात विदेश व्यापार नीति में अधिसूचित और निम्न सारणी में उल्लिखित प्रयोगशालाओं और एजेंसियों (एतश्मिन पश्चात् जिन्हें उक्त प्रयोगशालाओं और एजेंसियों से संदर्भित किया गया है) के द्वारा (ग्रेडिंग या प्रमाणन या भारत से पुनः निर्यात के लिए) किया गया हो, उस पर लगाये जाने वाले सीमा-शुल्क जो कि उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं से पूर्णतया छूट, निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर, प्रदान करती है, यथा :—

सारणी

क्र.सं.	प्रयोगशाला/ एजेंसी का नाम
1.	जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (GIA), मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया
2.	इंडिया डायमण्ड इंस्टीट्यूट, सूरत, गुजरात, इंडिया
3.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायमण्ड ग्रेडिंग एंड रिसर्च इंडिया प्रा. लि., सूरत, गुजरात, इंडिया

- (i) उक्त प्रयोगशालाएं और एजेंसियां आयात पत्तन के सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त/उप-आयुक्त, सीमा-शुल्क की संतुष्टि के तक एक सामान्य बंधपत्र भरेगी जिसमें यह वचन देंगे कि इन हीरों का समुचित लेखा-जोखा रखा जाएगा और

- प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 4.75 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और प्रक्रिया पुस्तिका के उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित अवधि के भीतर पुनः निर्यात कर दिया जाएगा;
- (ii) आयात की बिल ऑफ एंट्री के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हीरे के प्रत्येक नग के आकार, भार, रंग, कैरेट्स, विनिर्दिष्टिकरण, लगभग कीमत इत्यादि सहित हीरों का विस्तृत विवरण होगा;
 - (iii) बिल ऑफ एंट्री में “केवल प्रमाणन और ग्रेडिंग के लिए” पृष्ठांकन होना चाहिए;
 - (iv) उक्त सभी प्रयोगशालाएं और एजेंसियां, उनकी यूनिट में हीरे ले जाने के लिए तथा उनकी पहचान के प्रयोजन हेतु “यूनिक कंट्रोल नं.” आवंटित करेंगी और ऐसे हीरों के लिए अलग खाते का रख-रखाव करेंगी;
 - (v) ग्रेडिंग अथवा प्रमाणन के पश्चात हीरों को शिपिंग बिल के अंतर्गत पुनर्निर्यात किया जाएगा जैसा कि आयात के समय विस्तृत विवरण में उल्लेख किया गया था;
 - (vi) बिल आफ एंट्री का क्रॉस संदर्भ शिपिंग बिल में पृष्ठांकित किया जाएगा;
 - (vii) उक्त प्रयोगशालाएं और अभिकरण, शिपिंग बिल के साथ इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि पुनः निर्यात किए जा रहे हीरे वहीं हैं जिनका आयात किया गया था;
 - (viii) उक्त प्रयोगशालाएं और अभिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार आयात और पुनः निर्यात के संबंध में गारंटेड रेसीटेंस (GR) प्राप्त करेंगी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवा प्रभारों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगी;
 - (ix) सीमा-शुल्क अधिकारी, उक्त प्रयोगशालाओं और अभिकरणों की लेखा-परीक्षा और जांच-पड़ताल के लिए उनके परिसरों का दौरा कर सकते हैं;
 - (x) प्रमाणन अथवा ग्रेडिंग के लिए आयात किए गए हीरों का, उनके आयात की तारीख के 3 माह के भीतर पुनः निर्यात किया जाएगा;
 - (xi) उक्त प्रयोगशालाएं और अभिकरण, किसी तिमाही विशेष के अगले माह की 25 तारीख तक एक तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगे तथा इस तिमाही विवरणी में बिल आफ एंट्री, संख्या, तारीख, हीरों का ब्यौरा और पुनः निर्यात का ब्यौरा इत्यादि दर्शाया जाएगा; और
 - (xii) पुनः निर्यात की अनुमति उसी बंदरगाह से ली जाएगी जहां से आयात किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन से—

- (क) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को अधिसूचना सं. 1/2015-2020 के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है;
- (ख) “प्रक्रिया पुस्तिका” से अभिप्राय, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सार्वजनिक सूचना सं. 1/2015-2020 के अंतर्गत प्रकाशित, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तिका से है।

[फा. सं. डीजीईपी/जी एंड जे/428/2006]

आनन्द उपाध्याय, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2015

No. 40/2015-Customs

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cut and polished diamonds falling under Chapter 71 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported (for grading or certification and re-export out of India) by the laboratories and agencies (hereinafter referred to as the said laboratories and agencies) notified in the Foreign Trade Policy and mentioned in the Table below, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, subject to fulfillment of the following conditions, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of laboratory/agency
1.	Gemological Institute of America (GIA), Mumbai, Maharashtra, India
2.	Indian Diamond Institute, Surat, Gujarat, India
3.	International Institute of Diamond Grading & Research India Pvt. Ltd., Surat, Gujarat, India

- (i) the said laboratories and agencies shall furnish a general bond to the satisfaction of the Assistant Commissioner/Deputy Commissioner of Customs at the port of import, undertaking to properly account for the diamonds, to follow the procedure specified in paragraph 4.75 of the Handbook of Procedures and to re-export diamonds within the period as mentioned in the said paragraph of Handbook of Procedures;
- (ii) the import shall be allowed under bill of entry having the detailed description of the diamonds, including inter alia, the dimensions, weight, colour, caratage, specification, approximate value, etc. of each piece of diamonds;
- (iii) the bill of entry should carry the endorsement “only for certification and grading”;
- (iv) the said laboratories and agencies while taking the diamonds in their unit, shall allot a ‘unique control number’ for identification purposes and maintain a separate account for such diamonds;
- (v) after grading or certification, the diamonds shall be re-exported under a shipping bill containing the detailed description as was mentioned at the time of their import;
- (vi) cross reference of bill of entry shall be endorsed in the shipping bill;
- (vii) the said laboratories and agencies shall submit alongwith the shipping bill, a certificate to the effect that the diamonds being re-exported are the same as those imported;
- (viii) the said laboratories and agencies shall obtain Guaranteed Remittance (GR) waiver in respect of import and re-export as per the procedure laid down by the Reserve Bank of India (RBI) and realise the foreign exchange for the service charges in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines;
- (ix) the Custom Officers may visit the premises of the said laboratories and agencies for audit or checks;
- (x) the diamonds imported for certification or grading shall be re-exported within a period of three months from the date of their import;
- (xi) the said laboratories and agencies shall submit a quarterly statement by 25th of the month following the particular quarter and the statement shall reflect the bill of entry number, date, details of diamonds and details of re-export, etc.; and
- (xii) re-export shall be allowed only from the port through which import took place.

Explanation. - For the purposes of this notification,—

- (a) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2015 - 2020 notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification No. 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015;
- (b) “Handbook of Procedures” means the Handbook of Procedures notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1 vide Public Notice No. 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015.

[F. No. DGEP/G&J/428/2006]

ANAND UPADHAY, Under Secy.